महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन
(संलग्नित : ए.आय.एफ.ई.ई. व ए.आय.टी.यू.सी.)
नोंदणी क्र. ४३०९
नेल्सन चौक, सिताराम महाराज मंदीराजवळ, छावणी, नागपूर - ४४००१३
☎ २५९२१९१ (का)
९८२३०१९५३१ (मो)
E-mail : msewfnagpur@gmail.com
मोहन शर्मा, अध्यक्ष

क्र. प्रेस नोट नागपूर दिनांक २३.०४.२०२२

(मराठी प्रेस नोट का हिंदी अनुवाद))

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन

प्रेस नोट नागपुर 23.04.2022

बिजली की कमी नीति का संकट है!

कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण लोड शेडिंग का संकट है

महाराष्ट्र के 2 करोड़ 89 लाख उपभोक्ताओं और लोगों की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए राज्य में मौजूदा मांग 28,276 मेगावाट है। आज महानिर्मिति (जिसे महाजेनको भी कहा जाता है) कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 12,972 मेगावाट है। इसके अलावा, महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) में स्थापित क्षमता निजी कंपनियों की 5,785 मेगावाट, केंद्र की 5,952 मेगावाट और गैर-पारंपरिक स्रोतों की 8,140 मेगावाट है, अर्थात कुल 32849 मेगावाट है। मांग 28,276 मेगावाट की है। कोयले से बिजली पैदा करने के लिए महानिर्मिति कंपनी के पास 27 सेट हैं। आज यदि इन 27 सेटों में से हम अपवाद के रूप में नाशिक से केवल एक सेट को अलग रखते हैं, तो 26 सेट बिजली पैदा कर रहे हैं। अगले दो दिनों में नाशिक सेट भी पैदा करना शुरू करेगा। यह कथन गलत है कि महानिर्मिति कंपनी के सेट रखरखाव और मरम्मत के कारण चालू

नहीं हैं । इस कारण कोई सेट बंद नहीं है। जबकि स्थापित क्षमता 9,540 मेगावाट है, महानिर्मिति के ताप बिजली उत्पादन सेट 7,275 मेगावाट उत्पादन कर रहे हैं, और कर्मचारी, इंजीनियर और अधिकारी इस भीषण गर्मी में इसे 8,000 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

<u>महाराष्ट्र में कोयले से बिजली पैदा करने वाले सेटों की कुल संख्या</u>

नम्बर		सेटों की संख्या	मेगा वाट में कुल क्षमता
1	कोराडी थर्मल पावर स्टेशन	4	2190
2	खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन	5	1340
3	पारस थर्मल पावर स्टेशन	2	500
4	भुसावल थर्मल पावर स्टेशन	3	1210
5	नासिक थर्मल पावर स्टेशन	3	630
6	पराली थर्मल पावर स्टेशन	3	750
7	चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	7	2930
	कुल	**27**	**9550**

<u>आयात कोई समाधान नहीं है</u>

देश में कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह परिस्थिति केंद्र सरकार की नीति के साथ-साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की घटिया कार्यप्रणाली के कारण है। जब देश में उपलब्धता होती है, तो आयात न तो उचित होता है और न ही समर्थन के योग्य। इसका समाधान कोयले पर नीति, उत्पादन का लक्ष्य और कोयले के परिवहन के लिए रेलवे वैगनों का विशेष प्रावधान है। जो हमारा है उसे भूलकर किसी और के पीछे भागना (आयात करना) छोड़ देना चाहिए।

27 सेटों से बिजली पैदा करने के लिए महाराष्ट्र की बिजली उत्पादन कंपनी को कम से कम 1,40,000 मेट्रिक टन कोयले की जरूरत है। हालाँकि आज कोयले की दैनिक उपलब्धता केवल 1,10,000 मेट्रिक टन है। इसका मतलब है कि 30,000 मेट्रिक टन की कमी है, जिसके कारण ताप (कोयले से) बिजली पैदा करने वाले सेट अपनी पूरी स्थापित क्षमता पर काम और उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, बिजली उत्पादन केंद्रों को आपूर्ति किया जाने वाला कोयला घटिया है। इसमें कंकड़ और मिट्टी मिली हुई है। यही कारण है कि बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक कैलोरी मान में कमी है। कंकड़ और मिट्टी भी बॉयलर में प्रवेश करते हैं और उपकरण को नुकसान पहुंचाते है, जिस से उत्पादन पर असर होता है।

केंद्र सरकार की गलत कोयला नीति के कारण न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश के 12 राज्यों में बिजली उत्पादन का संकट पैदा कर दिया है।

संकट गलत नीति के कारण है।

हालांकि देश में कोयले का भरपूर भंडार है, लेकिन थर्मल पावर स्टेशनों को सात दिनों का स्टॉक नहीं मिलता है। इसका कारण राष्ट्रीय स्तर पर कोयला उद्योग को नियंत्रित करने वाली केंद्रीय नीति है। यह इंगित करता है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों को सही ढंग से विनियमित नहीं किया जाता है। हम कोयला उत्पादन में वृद्धि नहीं करते हैं, हम कोयले के परिवहन के लिए वैगनों की आपूर्ति में कमी करते हैं। यह कोई प्राकृतिक कमी नहीं है बल्कि नीति की असफलता है। केंद्र सरकार की निजीकरण नीति के चलते 43 ब्लॉकों में कोयले का खनन और उत्पादन निजी कंपनियों को सौंप दिया गया। ये निजी कंपनियां पूरी तरह विफल हो चुकी हैं और इनका कोयला उत्पादन 89 मिलियन टन तक सीमित है।

देश में खनन और उत्पादित कोयले की मात्रा 750 मिलियन टन है। इसमें से 16% निजी कंपनियों का है। हालांकि ये सभी निजी कंपनियां उत्पादन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई हैं और इनका उत्पादन 89 मिलियन टन तक सीमित है। इसलिए कोयले की कमी है और यह नीति की विफलता का एक उदाहरण है।

मजदूर 43 डिग्री गर्मी में कोयले में मेहनत करते हैं।

महाजेनको थर्मल पावर स्टेशनों के कर्मचारी, इंजीनियर और अधिकारी बिजली उत्पादन को अधिकतम करने के लिए भयंकर गर्मी के साथ-साथ बॉयलरों द्वारा उत्पादित आग और गर्मी के पास भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए पुराने सेट से भी प्रोडक्शन संभव हो पाया है।

निजी बिजली कंपनियों की नजर महावितरण (महाराष्ट्र स्टेट एलेक्ट्रिक्टी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड, MSEDCL) पर है।

महाराष्ट्र में अदानी पावर की स्थापित क्षमता 2,860 मेगावाट है। महावितरण के साथ अनुबंध के अनुसार, यह 2,100 मेगावाट की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है; परन्तु वह केवल 1,765 मेगावाट की आपूर्ति कर रही है। अदानी पावर ने महावितरण पर 20,000 करोड़ रुपये का दावा दर्ज किया है। बिजली की कमी के इस समय में, यह मुंबई से सटे ठाणे, रायगढ़ और नवी मुंबई को हथियाने के प्रयास में महावितरण को बदनाम करना चाहता है। बिजली उत्पादक कंपनियों में से चार निजी कंपनियां, आइडियल कंपनी, रतन इंडिया, नाशिक, REL और पायनियर, बुटीबोरी बिल्कुल भी बिजली का उत्पादन नहीं कर रही हैं।

<u>लोड शेडिंग से बचने के लिए महंगी बिजली खरीदी</u>

महाराष्ट्र के लोगों को लोड शेडिंग की समस्या से बचाने और 1,800 मेगावाट की कमी को पूरा करने के लिए महावितरण खुले बाजार में महंगी बिजली खरीद रहा है बिजली उपभोक्ताओं का महावितरण को बकाया के रूप में 65,000 करोड़ रु. है। इस कठिन परिस्थिति में वह लोड शेडिंग को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है।

हस्ताक्षरित,

मोहन शर्मा,

अध्यक्ष